





















## पाक की बेचैनी

इस समय अफगानिस्तान के विदेश मंत्री सात दिवसीय भारत के दौरे पर आए हुए हैं। इस बीच ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि पाक व अफगानिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर इशारा करती है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में काफी अंदर घुसकर तहरीके तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) पर सर्जिकल स्ट्राइक की है। जाहिर है टीटीपी पर सर्जिकल स्ट्राइक तो एक बहाना लगती है असल मकसद इसके पीछे कुछ और लगता है। लगता है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ भारत की बढ़ती नजदीकी को पचा नहीं पा रहा है। हालांकि टीटीपी और पाक के बीच संघर्ष काइ नया नहीं है। टीटीपी को हमेशा पाकिस्तान अपने लिए खात्रा मानता है और वह यह आरोप भी लगाता रहता है कि उसको शह अफगानिस्तान से मिल रही है। ताजा मामले में भी यही कह रहा है कि टीटीपी के विस्तृत सैन्य कार्रवाई की है। इसी तरह अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने नई दिल्ली में प्रकारों के सामने विस्तार से बात की है। मुत्ताकी ने पाक पर आरोप लगाया और कहा कि उसने खुद ही अपने के बालाई इलाकों में सैन्य अभियान चलाकर हजारों लोगों को बेघर किया था, जिनमें से कई शरणार्थी के रूप में अफगानिस्तान में रह रहे हैं। मुत्ताकी ने बताया कि ये लोग पाक से आए हैं और अफगान धरती पर शरणार्थी बनकर रह रहे हैं और ये लोग तब आए थे जब अमेरिका और उसकी समर्थित सरकार अफगानिस्तान में थी, तब इन्हें जगह दी गई थी और अब ये लोग हमारी देखरेख में शांति से रह रहे हैं। मुत्ताकी का यह भी कहना था कि पाकिस्तान अफगान सीमा जिसे ड्यूरंड लाइन के नाम से भी जाना जाता है, 2400 किमी से ज्यादा लंबी है और इसको नियन्त्रित करना आसान नहीं है। उन्होंने याद दिलाया कि न इस चर्चे खां नियन्त्रित कर सका और न ही अंग्रेज। इसको ताकत के बलबूते नहीं संभाला जा सकता। उन्होंने चतावनभरे लपज में कहा कि पाक के पास बड़ी फौज और बेहतरीन खुफिया एंजेसी हैं पर भी वे इसे खुद क्यों नहीं रोक पा रहे हैं। इस समय करत और उसकी अरब के हस्तक्षेप से दोनों देशों के बीच कोई सैन्य कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन मुत्ताकी ने साफ कहा कि अगर पाक शांति व अच्छे रिसेट नहीं तो अफगानिस्तान के पास और भी विकल्प मौजूद है, लेकिन अफगानिस्तान शांति में विश्वास रखता है। बड़ी बात मुत्ताकी ने कही वह यह है कि पाक अपने यहा आतंकी समूहों को बांध कर नहीं कर पा रहा है और अपने ही लोगों का खतरे में डालकर कुछ लोगों को खुश करने की क्यों कोशशा कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ ताकतें दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा रही हैं। जहां तक बात भारत की है, अफगानिस्तान के साथ इस तरह की पहल बेहतर संबंधों को उसने की है व अफगान विदेश मंत्री ने उसको सराहा है यह बड़ी सफलता है।

## निजी कॉलेज परिसर में सुरक्षा सुनिश्चित करें

पश्चिम बंगाल के दुगापुर में मेडिकल छात्रों के बावात चांकों के बाली है, हमारे सरकार ऐसी घटनाओं को बिल्कुल बदाश्न नहीं करती, वारतात में शामिल तीन अंग्रेजी प्रिफरेंस कर लिए गए हैं, युलिस अन्य की तलाश कर रही है, किसी को भी बद्धा नहीं जाएगा, निजी कॉलेजों को परिसर के भीतर और आपसमें सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाही तो वह लड़के निजी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही थी, इसलिए निजी मेडिकल कॉलेज बातों के बारे पर तीन सप्ताह पहले सम्ब्रह तर पर तीन लड़कियों के साथ बलाकार हुआ, औडिशा सरकार ने क्या कार्रवाई की और बगाल में आग महिलाओं के साथ कुछ भी होता है तो हम इसे सामान्य मामला नहीं मानते, यह एक गंभीर मामला है।

-ममता बनर्जी, सीएम, पश्चिम बंगाल

**इ**स वर्ष देश भर में हुई भारी बारिशों और जल संकट अब कोई दूर की आशंका नहीं, बल्कि एक कठोर सच्चाई बन चुका है। दिल्ली, मुंबई, चंन्द्र, बैगलूरु जैसे महानगर, जो आर्थिक प्रगति और आधुनिक जीवनशैली के प्रतीक हैं, अब जल प्रबल के बावजूद भारत के शहरी क्षेत्रों में तीन बड़े मॉल और आपसमें की कलानिनीयों में पानी को सलाई पूरी तरह ठप हो जाने से यह संकट के फूर्खीयों में आया। इन प्रतिष्ठानों को बढ़ करने की नीवें इसलिए, आ गई है कि क्योंकि टैक्टैके से इनकी जल आपूर्ति रुक गई, जबकि भूल दोहरा (ग्राउंड वॉटर बोरिंग) पर पहले से ही एनजीटी ने प्रतिबंध लगा रखा है। यह रिश्तों के बीच अस्थाई तकनीकी समस्या नहीं, बल्कि एक गहरे प्रशासनिक और नैतिक संकट की ओर संकेत करती है। पिछले सात दशकों में खरबों रुपये जल प्रबंधन पर खर्च किए जाने के बावजूद ऐसा क्यों?

दिल्ली जैसे शहर में जहां जनसंख्या 2 करोड़ से अधिक है, जल आपूर्ति व्यवस्था लंबे समय से दबाव में है। दिल्ली जल बोर्ड के आकड़ों के अनुसार, शहर में प्रतिदिन करीब 1,000 मिलियन गैलन पानी की मांग है, जबकि भूल दोहरा (ग्राउंड वॉटर बोरिंग) पर पहले से ही एनजीटी ने प्रतिबंध लगा रखा है। यह रिश्तों के बीच अस्थाई तकनीकी समस्या नहीं, बल्कि एक गहरे प्रशासनिक और नैतिक संकट की ओर संकेत करती है। पिछले सात दशकों में खरबों रुपये जल प्रबंधन पर खर्च किए जाने के बावजूद ऐसा क्यों?

दिल्ली जैसे शहर में जहां जनसंख्या 2 करोड़ से अधिक है, जल आपूर्ति व्यवस्था लंबे समय से दबाव में है। दिल्ली जल बोर्ड के आकड़ों के अनुसार, शहर में प्रतिदिन करीब 1,000 मिलियन गैलन पानी की मांग है, जबकि भूल दोहरा (ग्राउंड वॉटर बोरिंग) पर पहले से ही एनजीटी ने प्रतिबंध लगा रखा है। यह रिश्तों के बीच अस्थाई तकनीकी समस्या नहीं, बल्कि एक गहरे प्रशासनिक और नैतिक संकट की ओर संकेत करती है। पिछले सात दशकों में खरबों रुपये जल प्रबंधन पर खर्च किए जाने के बावजूद ऐसा क्यों?

## जल संकट की दस्तक दिल्ली से दूर नहीं



तभी संभव है जब लोग खुद बदलाव का हिस्सा बनें। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग और ग्रे-वॉटर रीसाइक्लिंग जैसे उपाय व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर अपनाएं जा सकते हैं। मॉल्स और हाउसिंग सोसाइटीज में यह व्यवस्था अनिवार्य की जानी चाहिए, ताकि टैक्टैके पर निर्भरता घटे। दिल्ली की बतामन संकट के बीच वातावरण में एसी घटनाएं घटती हैं। अनेकों वर्षों में एसी घटनाएं घटती हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक, यदि ठोस कदम नहीं उठाए गए तो 2030 तक देश के आधे बड़े शहर 'जल-वीनी' क्षेत्रों की श्रेणी में आ सकते हैं। इसलिए अब सायर है कि सरकार और समाज दोनों में यह व्यवस्था अनिवार्य की जानी चाहिए, ताकि टैक्टैके पर निर्भरता घटे। अनेकों वर्षों में एसी घटनाएं घटती हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक, यदि ठोस कदम नहीं उठाए गए तो 2030 तक देश के आधे बड़े शहर 'जल-वीनी' क्षेत्रों की श्रेणी में आ सकते हैं। इसलिए अब सायर है कि सरकार और समाज दोनों में यह व्यवस्था अनिवार्य की जानी चाहिए, ताकि टैक्टैके पर निर्भरता घटे। अनेकों वर्षों में एसी घटनाएं घटती हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक, यदि ठोस कदम नहीं उठाए गए तो 2030 तक देश के आधे बड़े शहर 'जल-वीनी' क्षेत्रों की श्रेणी में आ सकते हैं। इसलिए अब सायर है कि सरकार और समाज दोनों में यह व्यवस्था अनिवार्य की जानी चाहिए, ताकि टैक्टैके पर निर्भरता घटे। अनेकों वर्षों में एसी घटनाएं घटती हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक, यदि ठोस कदम नहीं उठाए गए तो 2030 तक देश के आधे बड़े शहर 'जल-वीनी' क्षेत्रों की श्रेणी में आ सकते हैं। इसलिए अब सायर है कि सरकार और समाज दोनों में यह व्यवस्था अनिवार्य की जानी चाहिए, ताकि टैक्टैके पर निर्भरता घटे। अनेकों वर्षों में एसी घटनाएं घटती हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक, यदि ठोस कदम नहीं उठाए गए तो 2030 तक देश के आधे बड़े शहर 'जल-वीनी' क्षेत्रों की श्रेणी में आ सकते हैं। इसलिए अब सायर है कि सरकार और समाज दोनों में यह व्यवस्था अनिवार्य की जानी चाहिए, ताकि टैक्टैके पर निर्भरता घटे। अनेकों वर्षों में एसी घटनाएं घटती हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक, यदि ठोस कदम नहीं उठाए गए तो 2030 तक देश के आधे बड़े शहर 'जल-वीनी' क्षेत्रों की श्रेणी में आ सकते हैं। इसलिए अब सायर है कि सरकार और समाज दोनों में यह व्यवस्था अनिवार्य की जानी चाहिए, ताकि टैक्टैके पर निर्भरता घटे। अनेकों वर्षों में एसी घटनाएं घटती हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक, यदि ठोस कदम नहीं उठाए गए तो 2030 तक देश के आधे बड़े शहर 'जल-वीनी' क्षेत्रों की श्रेणी में आ सकते हैं। इसलिए अब सायर है कि सरकार और समाज दोनों में यह व्यवस्था अनिवार्य की जानी चाहिए, ताकि टैक्टैके पर निर्भरता घटे। अनेकों वर्षों में एसी घटनाएं घटती हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक, यदि ठोस कदम नहीं उठाए गए तो 2030 तक देश के आधे बड़े शहर 'जल-वीनी' क्षेत्रों की श्रेणी में आ सकते हैं। इसलिए अब सायर है कि सरकार और समाज दोनों में यह व्यवस्था अनिवार्य की जानी चाहिए, ताकि टैक्टैके पर निर्भरता घटे। अनेकों वर्षों में एसी घटनाएं घटती हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक, यदि ठोस कदम नहीं उठाए गए तो 2030 तक देश के आधे बड़े शहर 'जल-वीनी' क्षेत्रों की श्रेणी में आ सकते हैं। इसलिए अब सायर है कि सरकार और समाज दोनों में यह व्यवस्था अनिवार्य की जानी चाहिए, ताकि टैक्टैके पर निर्भरता घटे। अनेकों वर्षों में एसी घटनाएं घटती हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक, यदि ठोस कदम नहीं उठाए गए तो 2030 तक देश के आधे बड़े शहर 'जल-वीनी' क्षेत्रों की श्रेणी में आ सकते हैं। इसलिए अब सायर है कि सरकार और समाज दोनों में यह व्यवस्था अनिवार्य की जानी चाहिए, ताकि टैक्टैके पर निर्भरता घटे। अनेकों वर्षों में एसी घटनाएं घटती हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक, यदि ठोस कदम नहीं उठाए गए तो 2030 तक देश के आ

